

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 18 मई, 2009

विषय:-मै0 गोल्ड प्लस ग्लास इन्डस्ट्रीज को ग्राम थथौला व थथौला खेमपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में औद्योगिक प्रयोजन हेतु कुल 3.7565 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2210/भूमि व्यवस्था-भू0क्र0 दिनांक-13.12.08 एवं पत्र संख्या-920/भूमि व्यवस्था दिनांक-27.10.08 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 गोल्ड प्लस ग्लास इन्डस्ट्रीज लि0 दिल्ली को आपके उपरोक्त पत्रों द्वारा संस्तुत किये गये क्षेत्रफल क्रमशः 1.964 है0 एवं 0.9070 है0 तथा 0.8855 है0 अर्थात् कुल क्षेत्रफल 3.7565 है0 भूमि ग्राम थथौला एवं थथौला खेमपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में ग्लास इन्डस्ट्रीज की स्थापना हेतु क्रय की अनुमति उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत आपके उपरोक्त पत्र के द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओं के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- 1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (ग्लास इन्डस्ट्री) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है

अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विकय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- शासन द्वारा दी गई भूमि कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7- भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक सहायता सचिवालय से आशय पत्र एवं उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8- यदि प्रस्तावित मे से आई0ओ0सी0 द्वारा भूमि उपयोग (अर्जन) का अधिकार अधिकृत किया गया है तो उस भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण एवं खुदाई पाईप लाईन एक्ट की धारा-15 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्राविधान उक्त इकाई पर लागू होंगे।

9- इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 के डिपों प्रस्तावित भूमि के निकट है। अतः अग्नि शमन विभाग की भी अनापत्ति प्राप्त की जानी होगी।

10- औद्योगिक आस्थान के नियोजन के अनुरूप ही प्रस्तावित उद्योग स्थापित किया जायेगा।

11- राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बायलॉज के आधार पर ही उद्योग का निर्माण किया जायेगा।

10- प्रस्तावित उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

11- सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

12- किसी भी दशा में प्रस्तावित कंताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा

न हो इसके लिये भूमि कय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

13- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

14- योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/ संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।

15- उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन हाने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त करदी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

पू०प०सं०-1234(1)/संमदिनांकित/2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश के उद्योग विभाग से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
- 3- सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 5- निदेशक, उद्योग, इन्ड्रिस्ट्रियल इस्टेट, पटेलनगर, देहरादून।
- 6- सदस्य सचिव उत्तराखण्ड पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
- 7- प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम, प्रा०लि० देहरादून।
- 8- श्री सुरेश त्यागी निदेशक गोल्ड प्लस ग्लास इन्डस्ट्रीज लि० जी०-192 प्रशान्त विहार दिल्ली।
- 9- निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
- 10- प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बड़ोनी)
अनु सचिव।